

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

नयी औद्योगिक नीति की निर्माण प्रक्रिया

Posted On: 29 AUG 2017 12:32PM by PIB Delhi

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और प्रोत्साहन विभाग ने मई 2017 में नयी औद्योगिक नीति बनाने की प्रिक्रया प्रारम्भ की थी। 1991 में घोषित औद्योगिक नीति के पश्चात भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। पिछले तीन वर्षों में अर्थव्यवस्था के मजबूत आधार स्तंभों तथा अति महत्त्वपूर्ण सुधारों के परिणाम स्वरूप भारत विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाले भारतीय उद्योग के लिए नए विचार और रणनीतियां लागू करने के लिए तैयार है। नयी औद्योगिक नीति में राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भी शामिल की जाएगी।

औद्योगिक नीति के निर्धारण में विचार-विमर्श की नीति अपनाई गई है। इसके अंतर्गत 6 विषयों से संबंधित विशिष्ट समूह बनाये गए और इनपुट एराप्त करने के लिए डीआईपीपी के वेबसाइट पर एक ऑनलाइन सर्वे किया गया। सरकारी विभागों, उद्योग परिसंघों, शिक्षा जगत के एरितिनिधियों तथा विशेषज्ञों को विशिष्ट समूहों का सदस्य.बनाया गया है। ये समूह, उद्योग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सामना की जाने वाली चुनौतियों का अध्ययन करेंगे। 6 विशिष्ट क्षेत्र निम्न हैं:- विनिर्माण और लघु, छोटे व मझौले उद्यम (एमएसएमई), तकनीक और नवोन्मेष, व्यापार करने में आसानी, आधारभूत संरचना, निवेश, व्यापार और वित्तीय नीति तथा कौशल व भविष्य के लिए रोजगार उपलब्धता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के संदर्भ में भारत के आर्थिक रूपांतरण के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है जो नीति-निर्माण के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करेगा।

'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहित करने के साथ ही नयी औद्योगिक नीति का उद्देश्य भारत को विनिर्माण का केन्द्र बनाना है। इसके अंतर्गत तकनीकी रूप से आधुनिक विनिर्माण के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), कृति्रम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स जैसे अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया है।

केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती निर्मला सीता रमन उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों तथा चेन्नई, गुवाहाटी और मुम्बई की राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करेंगी। अक्टूबर, 2017 में नयी औद्योगिक नीति की घोषणा संभावित है।

डीआईपीपी ने नयी नीति निर्माण के लिए लोगों से विचार, फीडवैक और सुझाव आमंति्रत किये हैं। इस संदर्भ में एक परिचर्चा प्रपत्र यहां संलग्न है। नयी औद्योगिक नीति के संबंध में डीआईपीपी को दिये जाने वाले सभी विचार व सुझाव 25 सितम्बर 2017 तक kokila.jayram@nic.in या jsvk-dipp@nic.in पर भेजे जा सकते हैं।

वीके/जेके/एल - 3570

(Release ID: 1501100) Visitor Counter: 16









in